

महिलाएँ, व्यवसाय और कानून 2024

प्रलिस के लिये:

[आर्थिक सहयोग और विकास संगठन](#), [लगिभेद](#), [महिला](#), [व्यवसाय और कानून 2024](#), [वशिव बैंक](#)

मेन्स के लिये:

महिला, व्यवसाय और कानून 2024, भारत और वशिव में महिलाओं से संबंधित मुद्दे एवं मानव संसाधन के विकास पर इसका प्रभाव ।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वशिव बैंक](#) समूह ने “महिला, व्यवसाय और कानून 2024” शीर्षक से एक रपिर्ट जारी की है, जिसमें वैश्विक कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश में बाधा डालने वाली चुनौतियों जो उनकी, परिवार की और उनके समुदाय की समृद्धि में योगदान करने की उनकी क्षमता में बाधा बन रही हैं, का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है ।

महिला व्यवसाय और कानून- 2024 रपिर्ट क्या है?

- इसके सूचकांक कानून और सार्वजनिक नीति के क्षेत्रों व उन आर्थिक नरिणियों से संबंधित हैं जो महिलाएँ अपने जीवन तथा करियर के दौरान लेती हैं । यह अभिनिरिधारति करती हैं कि कहां और कनि क्षेत्रों में महिलाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ता है ।
- संकेतक:** इसमें 10 संकेतक हैं- सुरक्षा, गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, बाल देखभाल, विवाह, पतिव, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन ।
 - हिसा से सुरक्षा और बाल देखभाल सेवाओं तक पहुँच अत्यंत महत्त्वपूर्ण संकेतक हैं ।

रपिर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- कानूनी फरेमवरक सूचकांक:**
 - [आर्थिक सहयोग और विकास संगठन](#) की उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में से 11 ने 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त किये जिसमें **इटली 95 अंकों के साथ अग्रणी** है, इसके बाद **न्यूजीलैंड तथा पुर्तगाल ने 92.5 अंक** प्राप्त किये ।
 - इसके विपरीत, 37 से अधिक अर्थव्यवस्थाएँ **महिलाओं को पुरुषों द्वारा प्राप्त आधे से भी कम कानूनी अधिकार** प्रदान करती हैं, जिससे लगभग आधा अरब महिलाएँ प्रभावित होती हैं । विशेष रूप से, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं का **औसत स्कोर 75.4** है ।
 - उच्च-मध्यम-आय अर्थव्यवस्थाएँ लगभग 66.8 के औसत स्कोर के नकिट हैं । उच्चतम और नमिनतम स्कोरिंग अर्थव्यवस्थाओं के बीच स्कोर का अंतर उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक स्पष्ट है, जिसमें 75 अंकों का पर्याप्त अंतर है ।
- महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम कानूनी अधिकार प्राप्त हैं:**
 - जब हिसा और बच्चों की देखभाल से जुड़े कानूनी मतभेदों को ध्यान में रखा जाता है, तो **वशिव भर में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी सुरक्षा** मिलती है । यह **77% के पछिले अनुमान से भी कम** है ।
- महिलाओं के लिये कानूनी सुधारों और वर्तमान परिणामों के बीच अंतर:**
 - भले ही कई देशों ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानून बनाए हैं, **लेकिन इन कानूनों और महिलाओं के वर्तमान अनुभवों के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर** है ।
 - 98 अर्थव्यवस्थाओं ने समान मूल्य के काम के लिये महिलाओं हेतु समान वेतन अनविर्य करने वाला कानून बनाया है ।**
 - फरि भी **केवल 35 अर्थव्यवस्थाएँ**, प्रत्येक पाँच में से एक से भी कम, **नेवेतन अंतर को दूर करने के लिये वेतन-पारदर्शिता उपायों को अपनाया है ।**
- देशों द्वारा खराब प्रदर्शन:**
 - टोगो (Togo) उप-सहारा अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी रहा है, जिसने ऐसे कानून बनाए हैं** जो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले लगभग **77% अधिकार प्रदान करते हैं**, जो महाद्वीप के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है ।

- फरि भी टोगो ने अब तक पूर्ण कार्यान्वयन के लिये आवश्यक केवल 27% प्रणालियाँ स्थापित की हैं।
- यह दर उप-सहारा अर्थव्यवस्थाओं के लिये औसत है।
- वर्ष 2023 में सरकारें कानूनी समान अवसर सुधारों, वेतन, माता-पिता के अधिकार और कार्यस्थल सुरक्षा की तीन श्रेणियों को आगे बढ़ाने में मुखर थीं।
- फरि भी, लगभग सभी देशों ने पहली बार ट्रैक की जा रही दो श्रेणियों - बच्चों की देखभाल तक पहुँच और महिला सुरक्षा, में खराब प्रदर्शन किया।
- **महिला सुरक्षा:**
 - सबसे बड़ी कमज़ोरी महिला सुरक्षा है, जिसका वैश्विक औसत स्कोर सरिफ 36 है। महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह और सत्री हत्या के खिलाफ आवश्यक कानूनी सुरक्षा का बमुश्किल एक तहियाँ हिससा प्रापूत है।
 - हालाँकि 151 अर्थव्यवस्थाओं में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को प्रतर्बिधति करने वाले कानून हैं, केवल 39 अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक स्थानों पर इसे प्रतर्बिधति करने वाले कानून हैं। यह अक्सर महिलाओं को काम पर जाने के लिये सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से रोकता है।
- **बाल देखभाल:**
 - महिलाएँ पुरुषों की तुलना में प्रतदिनि औसतन 2.4 घंटे अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य में बतियाती हैं, जिसमें से अधिकांश बच्चों की देखभाल पर खर्च होता है।
 - केवल 78 अर्थव्यवस्थाएँ, यानी आधे से भी कम, छोटे बच्चों वाले माता-पिता को कुछ वतित्तीय या कर सहायता प्रदान करती हैं।
 - केवल 62 अर्थव्यवस्थाओं, एक तहियाँ से भी कम, में बाल देखभाल सेवाओं को नयित्तरति करने वाले गुणवत्ता मानक हैं, जिनके बनिा महिलाएँ काम पर जाने के बारे में दो बार सोच सकती हैं, जबकिउनकी देखभाल में बच्चे हैं।
- **महिलाओं के लिये कई बाधाएँ:**
 - महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरणतः उद्यमता के क्षेत्र में, प्रतयेक पाँच अर्थव्यवस्थाओं में से केवल एक ही सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं के लिये लगी-संवेदनशील मानदंडों को अनविर्य करती है, जिसका अर्थ है कि महिलाएँ बड़े पैमाने पर 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतविर्य के आर्थिक अवसर से वंचित हैं।
 - वेतन के संबंध में महिलाओं को पुरुषों को दिये जाने वाले प्रतयेक 1 अमेरिकी डॉलर पर केवल 77 सेंट का पारशिरमिक प्रापूत होता है। पुरुष तथा महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों में व्यापक अंतराल है। वशिव के 62 देशों में पुरुषों और महिलाओं के सेवानवित्त होने की आयु एक समान नहीं है।
 - महिलाओं का जीवनकाल पुरुषों की तुलना में अधिक होता है कति रोजगार में उन्हें अल्प वेतन मलित है, बच्चों के जन्म के उपरांत वे अवकाश लेती हैं और समय से पूरव सेवानवित्त हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पेंशन का अल्प लाभ तथा वृद्धावस्था में अधिक वतित्तीय असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

संबद्ध रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा?

- 74.4% स्कोर के साथ भारत की रैंक साधारण सुधार के साथ 113 हो गई। भारत का स्कोर वर्ष 2021 से स्थिर बना हुआ है कति इसकीरैंकगि वर्ष 2021 में 122 थी जो वर्ष 2022 में घटकर 125 और वर्ष 2023 सूचकांक में 126 हो गई।
- भारतीय महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 60% कानूनी अधिकार हैं जो वैश्विक परिदृश्य में औसत 64.2% से थोड़ा कम है।
 - हालाँकि भारत ने दक्षिण एशियाई देशों से बेहतर प्रदर्शन किया, जहाँ महिलाओं को पुरुषों द्वारा प्रापूत कानूनी सुरक्षा का केवल 45.9% प्रापूत है।
- महिलाओं के संबंध में अवगमन की स्वतंत्रता और विवाह से संबंधित बाधाओं के वषिय में भारत को पूर्ण अंक प्रदान किये गए।
- महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों का मूल्यांकन करने वाले संकेतक में भारत का स्कोर कम रहा।
 - संबद्ध वषिय में सुधार करने हेतु भारत समान कार्य के लिये समान वेतन अनविर्य करने, महिलाओं को पुरुषों के समान रात्र में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने तथा महिलाओं को पुरुषों के साथ समान स्तर पर औद्योगिक नौकरियों में शामिल होने में सक्षम बनाने के संबंध में नीतियों क्रयानवति कर सकता है।
- सहायक ढाँचे के वषिय में भारत ने वैश्विक और दक्षिण एशियाई देशों से अधिक अंक प्रापूत किये।

रिपोर्ट की अनुशंसाएँ क्या हैं?

- महिलाओं को कार्य करने अथवा व्यवसाय शुरू करने से बाधित करने वाले भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं का उनमूलन करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20% से अधिक की वृद्धि हो सकती है।
 - इसके परिणामस्वरूप आगामी दशक में वैश्विक विकास दर में दोगुना वृद्धि हो सकती है।
- समान अवसर कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन एक प्रापूत सहायक ढाँचे पर नरिभर करता है, जिसमें सुदृढ़ प्रवर्तन तंत्र, लगी-संबंधी वेतन असमानताओं का अनुवीक्षण करने के लिये एक प्रणाली और हिंसा से संरक्षित महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता शामिल है।
- कानूनों में सुधार के प्रयासों में तेज़ी लाना और सार्वजनिक नीतियों को लागू करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक है जो महिलाओं को कार्य करने तथा व्यवसाय प्रारंभ करने के साथ-साथ सक्षम बनाते हैं।
- महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना तथा उनकी आवाज़ को बुलंद करने के साथ ही उन्हें सीधे प्रभावित करने वाले नरिण्यों को आकार देने की कुंजी है।

??????:

प्रश्न. 'व्यापार करने की सुविधा के सूचकांक' में भारत की रैंकिंग समाचारों में कभी-कभी दखिती है। नमिनलखिति में से कसिने इस रैंकिंग की घोषणा की है? (2016)

- (a) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
- (b) विश्व आर्थिक मंच
- (c) विश्व बैंक
- (d) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर: (c)

प्रश्न. 'विश्व आर्थिक संभावना (ग्लोबल इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स)' रिपोर्ट आवधिक रूप से नमिनलखिति में से कौन जारी करता है? (2015)

- (a) एशिया विकास बैंक
- (b) यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट)
- (c) यू.एस. फेडरल रिज़र्व बैंक
- (d) विश्व बैंक

उत्तर: (d)

प्रश्न .3 नमिनलखिति में से कौन-सा संगठन 'विश्व आर्थिक आउटलुक' नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? (2014)

- (a) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (b) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
- (c) विश्व आर्थिक मंच
- (d) विश्व बैंक

उत्तर: (a)

प्रश्न. 'सतत वन परदृश्यों के लिये बायोकार्बन फंड पहल का प्रबंधन कसिके द्वारा कथिा जाता है। (2015)

- (a) एशियाई विकास बैंक
- (b) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
- (d) विश्व बैंक

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिसा के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से नपिटने के लिये कुछ अभनिव उपाय सुझाइये। (2014)

प्रश्न. भारत में समय और स्थान के वरिद्ध महिलाओं के लिये नरितर चुनौतियाँ क्या हैं? (2019)?